मशीनरी कानून को लागू करने के लिए बाध्य है, याचिकाकर्ता को आगे के निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता के बिना, प्रत्येक कॉपीराइट उल्लंघन के लिए जब किसी भी घटना में सार्वजनिक कलाकार (जिसमें एक विवाह समारोह शामिल होगा) कॉपीराइट सोसाइटी से लाइसेंस के बिना एक ध्वनि रिकॉर्डिंग को पुनः प्रस्तुत करता है।

IX. स्वभाव

(13) इन परिस्थितियों में, जहां तक यह याचिकाकर्ता-कंपनी को सरकार का प्रतिनिधित्व करने और सरकार से आगे के निर्देश या अधिसूचना की प्रतीक्षा करने का निर्देश देता है, विवादित पत्र रद्द कर दिया जाता है। सरकार से किसी नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है और न ही याचिकाकर्ता को विवादित पत्र में बताए गए तरीके से सरकार को कोई अभ्यावेदन देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पुलिस ऊपर बताए गए तरीके से कॉपीराइट उल्लंघन की वैध शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

(14) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों पर दी गई है।

ए. आगरवाल

के. कन्नन से पहले, जे.

कंवर सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ-2011 का उत्तरदाता सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7902

19 जुलाई, 2011

भारत का संविधान-Art.226/227 और 300A-विद्युत अधिनियम 2003-S. 67, 164, 165, 176, 185-1910 का विद्युत अधिनियम-धारा 12-टेलीग्राफ अधिनियम, 1885-धारा। 10 से 19-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस. 40 और 41-विद्युत नियम, 2005-विद्युत नियम, 1952-विद्युत कार्य नियम, 2006-आर. आई. 3 (बी) और 4-अपनी संपत्ति पर उच्च तनाव वाले तार बिछाने पर भूमि मालिक द्वारा आपत्ति-टेलीग्राफ अधिनियम के तहत

लाइसेंसधारी की शक्ति-भूमि मालिक द्वारा किसी भी आपत्ति की किसी भी गुंजाइश को हटा दें-पारेषण लाइन बिछाने की शक्ति के लिए हमेशा संपत्ति की मांग की आवश्यकता नहीं होती है-आवश्यकतानुसार मुआवजा टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्रदान किया जाएगा न कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत-लाइसेंसधारी की कार्रवाई कानून की पुष्टि करती है।

माना गया कि 9 दिसंबर 2010 के आदेश के तहत अधिसूचित संचरण योजना एक अंतर-राज्य संचरण लाइन है और इसलिए उपयुक्त प्राधिकरण केवल राज्य सरकार है। जब खंड 164 अनुज्ञप्तिधारक को टेलीग्राफ अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है, तो टेलीग्राफ लाइनों के संदर्भ को विद्युत लाइनों के लिए आवेदन के रूप में समझा जाना चाहिए और केंद्र सरकार को टेलीग्राफ लाइनों को स्थापित करने और बनाए रखने की शक्ति को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसका अर्थ राज्य सरकार को बिजली लाइनों को स्थापित करने और बनाए रखने की शक्ति है।

(पैरा 11) ने आगे कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया है कि किसी भी सरकारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया है।भविष्य के मार्गदर्शन के लिए एक उपाय के रूप में, मैं राज्य सरकार को निर्देश दूंगा कि वह आपत्तियों के लिए प्रावधान करे और प्रभावित पक्षों के लिए संचरण योजना का विवरण प्राप्त करे, जिसमें लाइसेंसधारियों को राज्य के भीतर गांवों या उनके आसपास के क्षेत्र में एक स्थानीय पता देने पर जोर दिया जाए जहां संचरण लाइनें बिछाई गई हैं।अभी तक, किसी भी कानूनी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए मुझे यह मानने का कोई कारण नहीं मिलेगा कि प्रतिवादी के कार्यों को दूषित किया गया है।

(पैरा 15) ने आगे कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक राय का पूर्व-जवाब देना भूमि मालिक की पूर्व सहमति के बिना मुख्य संचरण लाइनों को बिछाने की लाइसेंसधारी की शक्ति को बरकरार रखता है और मैं इस तरह के तर्क को बरकरार रखता हूं।(पैरा 17) याचिकाकर्ता की ओर से जयवीर यादव और अधिवक्ता श्री गुंगन मेहता के साथ अधिवक्ता संजीव कोडन।

महाराज कुमार, सुश्री शर्मिला शर्मा के लिए अधिवक्ता, 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7902 में भारत संघ के लिए अधिवक्ता

महाराज कुमार, सी. डब्ल्यू. पी. Nos.10163 और 2011 के 10236 में भारत संघ के अधिवक्ता

अजय कौशिक, भारत संघ के अधिवक्ता सी. डब्ल्यू. पी. 2011 का 9291,9268 और 11676।

ओ. पी. शर्मा, एडिशनल।ए. जी, हरियाणा।

मोहनीश शर्मा, नरेंद्र हुड्डा के वकील, प्रतिवादी Nos.3 और 4 के अधिवक्ता

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गोयल, अधिवक्ता, सुश्री शाक्य चौधरी, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता

615

कंवर सिंह बनाम भारत का संघ अन्य का संघ

(के. कन्नन, जे.)

के. कन्नन, जे. आई. सारांश

(1) उपरोक्त मामला और रिट याचिकाओं का समूह भूमि मालिकों के कहने पर है जो अपनी भूमि पर बिजली अधिनियम 2003 के तहत उच्च तनाव वाले तार बिछाने के लिए 5 वें प्रतिवादी, लाइसेंसधारी की कार्रवाई से व्यथित हैं।शिकायत यह है कि प्रतिष्ठानों को प्रासंगिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया है और इसलिए अपनी-अपनी रिट याचिकाओं द्वारा से अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी बिजली अधिनियम, 2003 के तहत कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना 400 केवी की उच्च पारेषण बिजली लाइनों को ऊपर नहीं रखेंगे और हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन किए बिना।अतिरिक्त प्रार्थनाएँ बारी-बारी से या इसके अलावा हैं कि ऊपर से पारेषण लाइनों को स्थापित करने के लिए संबंधित भूमि के उपयोग के लिए पूरा मुआवजा, किराया और अन्य आकस्मिक नुकसान दिया जाएगा।यह मामला विद्युत अधिनियम, 2003, विद्युत अधिनियम, 1910 के कुछ प्रावधानों की जांच करने का आह्वान करता है, जो खंड 185, टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, विद्युत नियम, 2005, विद्युत नियम, 1952 और विद्युत कार्य नियम, 2006 में बनाए गए कुछ अपवादों के अधीन पूर्व अधिनियम द्वारा निरस्त किए गए थे।निर्णय नोटिस की आवश्यकताओं, भूमि मालिकों द्वारा आपत्तियों की सीमा और राज्य के अधिकार के तहत संचालित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए लाइसेंसधारी की शक्ति को पार करता है और यह मानता है कि

रिट याचिकाओं के लिए औचित्य खोजने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों या नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है।

II. अनुज्ञप्तिधारी को शक्ति का विस्तार

(2) 9 दिसंबर 2010 को हरियाणा सरकार, बिजली विभाग द्वारा जारी एक आदेश द्वारा, झज्जर के. टी. ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय गुजरात के गांधीनगर में है, को पारेषण लाइनें बिछाने का लाइसेंस 5 वें प्रतिवादी को दिया गया था। यह (1) झज्जर-काबुलपुर (रोहतक), (2) काबुलपुर-दीपालपुर (सोनीपत), अब्दुल्लापुर-बवाना के लूप-इन-लूप-आउट सर्किट के बीच पारेषण योजना के लिए बिजली की खंड 68 के तहत मंजूरी का तात्पर्य है।आदेश में कहा गया है कि इस योजना में 100 किलोमीटर से अधिक कृषि भूमि पर पारेषण लाइनें, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, रेलवे लाइन, स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र आदि को पार करना शामिल है। आदेश में आगे कहा गया है कि लाइसेंसधारी के पास खंड के तहत सभी शक्तियां होंगी।

164 2003 के अधिनियम का, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास टेलीग्राफ अधिनियम के तहत है। आदेश में जिस सहमति पर विचार किया गया है, वह स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की सहमति है, जो पारेषण योजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं और बिजली अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक की मंजूरी के बाद इसे संचालित करते हैं।यह मंजूरी 25 साल की अवधि के लिए है।

III. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्रावधान जो लाइसेंसधारी की शक्तियों और 'उपयुक्त सरकार' द्वारा शक्ति को विनियमित करने की सीमा से संबंधित हैं।

(क) केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति और इसके अंतर्गत आने वाला विषय

(3) विभिन्न उद्देश्यों के लिए नियम निर्धारित करने की केंद्र सरकार की शक्ति 2003 के अधिनियम की खंड 176 द्वारा शासित होती है। जहां तक संचरण लाइनों के लिए प्रासंगिक है, इस खंड की भाषा निम्नलिखित शब्दों में निहित हैः

“176(1):केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(ई) खंड 67 की उप-खंड (2) के तहत मालिक या अधिभोगकर्ता की संपत्ति को प्रभावित करने वाले लाइसेंसधारियों के कार्य;

(च) ऐसे अन्य मामले जो खंड 68 की उप-खंड (2) के खंड (ग) के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं;

संबंधित प्रावधानों को उस विषय की जांच करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकते हैंः

खंड 67.सड़कों, रेलवे आदि को खोलने का प्रावधान। (1)।

(2) उपयुक्त सरकार, इस संबंध में अपने द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है -

(क) वे मामले और परिस्थितियाँ जिनमें कार्य करने के लिए उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, मालिक या अधिभोगकर्ता की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी;

(ख) प्राधिकरण जो उन परिस्थितियों में अनुमति दे सकता है जहां मालिक या अधिभोगकर्ता कार्यों को पूरा करने पर आपत्ति करता है;

(ग) कार्य पूरा करने से पहले लाइसेंसधारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की प्रकृति और अवधि;

(घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने की प्रक्रिया और तरीका;

(ई) इस धारा के तहत कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे या किराए का निर्धारण और भुगतान;

(च) आपात स्थिति होने पर की जाने वाली मरम्मत और कार्य;

(छ) इस खंड के तहत कुछ कार्यों को करने का मालिक या अधिभोगकर्ता का अधिकार और इसलिए खर्चों का भुगतान;

(ज) नालियों, पाइपों या अन्य विद्युत लाइनों या कार्यों के पास अन्य कार्यों को करने की प्रक्रिया;

((i) पाइपों, विद्युत लाइनों, विद्युत संयंत्रों, तार लाइनों, सीवर लाइनों, सुरंगों, नालियों आदि की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया।

(जे) सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, सीवर, नालियों या सुरंगों पर कार्यों से संबंधित बाड़ लगाने, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया और उनकी तत्काल बहाली;

(के) ऐसे कार्यों से सार्वजनिक उपद्रव, पर्यावरणीय क्षति और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को अनावश्यक नुकसान से बचना;

((च) ऐसे कार्य करने की प्रक्रिया जो उपयुक्त सरकार, अनुज्ञप्तिधारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं;

((ट) किसी भी रेलवे, ट्राम मार्ग, जल मार्ग आदि की बहाली के लिए आवश्यक राशि जमा करने का तरीका;

(एन) ऐसे कार्यों से प्रभावित संपत्ति की बहाली और उसके रखरखाव का तरीका;

(ओ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय क्षतिपूर्ति जमा करने और प्रतिभूति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया; और

(पी) ऐसे अन्य मामले जो इस खंड के तहत कार्यों के निर्माण और रखरखाव के लिए आकस्मिक या परिणामी हैं।

68. ऊपर की रेखाएँ।— (1) एक ओवरहेड लाइन, पूर्व के साथ

उपयुक्त सरकार का अनुमोदन, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार जमीन के ऊपर स्थापित या स्थापित किया जाए।

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे-(ए) एक ऐसी विद्युत लाइन के संबंध में जिसका नाममात्र वोल्टेज 11 किलोवोल्ट से अधिक नहीं है और जिसका

उपयोग एकल उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है या जिसका उपयोग करने का इरादा है;

((ख) विद्युत लाइन के इतने हिस्से के संबंध में जो इसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में परिसर के भीतर है या होगा; या

((ग) ऐसे अन्य मामलों में, जो विहित किए जाएं।

(3) उपयुक्त सरकार, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन देते समय, ऐसी शर्तें (लाइन के स्वामित्व और संचालन के बारे में शर्तों सहित) लगाएगी जो उसे आवश्यक लगती हैं।

(4) उपयुक्त सरकार ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय अनुमोदन को बदल या रद्द कर सकती है जो उसके द्वारा दिए गए अनुमोदन में निर्धारित किया जाए।

(5) जहां कोई पेड़ किसी ऊपरी रेखा के पास खड़ा है या पड़ा है या जहां कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी रेखा लगाने के बाद एक ऊपरी रेखा के पास रखी गई है या गिर गई है, बाधित करती है या हस्तक्षेप करती है, या बाधित करने या हस्तक्षेप करने की संभावना है, ऐसी रेखा की स्थापना, बाधित या हस्तक्षेप करती है 619

कंवर सिंह बनाम भारत का संघ अन्य का संघ

(के. कन्नन, जे.)

बिजली के परिवहन या संचरण या किसी भी काम की पहुंच में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने की संभावना के साथ, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या प्राधिकरण, लाइसेंसधारी के आवेदन पर, पेड़, संरचना या वस्तु को हटा सकता है या अन्यथा व्यवहार कर सकता है जैसा वह उचित समझता है।

(6) उप-धारा (5) के तहत किसी आवेदन का निपटान करते समय, उस उप-धारा के तहत निर्दिष्ट एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या प्राधिकरण, ऊपरी रेखा लगाने से पहले मौजूद किसी भी पेड़ की स्थिति में, पेड़ में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ऐसा मुआवजा प्रदान करेगा जो वह उचित समझता है, और ऐसा व्यक्ति लाइसेंसधारी से उसी की वसूली कर सकता है।स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वृक्ष" अभिव्यक्ति में कोई झाड़ी, बाड़, जंगल की वृद्धि या अन्य पौधा शामिल माना जाएगा।

(ख) खंड 67 (2) के साथ पठित खंड 176 (2) के तहत बनाए गए नियम।

(4) केंद्र सरकार ने लाइसेंसधारियों के कार्य नियम 2006 (जिसे 2006 नियम कहा जाता है) तैयार किया है जो नियम 3 (बी) द्वारा से प्रदान करता है कि जहां भवन या भूमि का मालिक या अधिभोगकर्ता इस नियम के तहत किए जाने वाले कार्यों के संबंध अन्य बातों के साथ साथ आपत्तियां उठाता है, तो लाइसेंसधारी जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या उस ओर से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करेगा।उप-नियम 2 जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद मुआवजा तय करने का अधिकार देता है।उप-नियम 4 लाइसेंसधारक को 2006 के नियमों में निहित परिसीमनों से मुक्त करता है और अधिनियम की खंड 164 के तहत जारी आदेश के तहत प्रदान की गई सीमा तक अपनी शक्तियों का मार्गदर्शन इन शब्दों द्वारा करता हैः

" इस नियम में निहित कुछ भी प्रदत्त शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

अधिनियम की खंड 164 के तहत किसी भी लाइसेंसधारी पर।

(ग) खंड 164 के तहत जारी लाइसेंसधारी की शक्ति 2006 के नियमों के तहत सीमाओं को ग्रहण करती है।

(5) हम राज्य सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2010 को लाइसेंसधारी को निर्दिष्ट स्थानों के बीच पारेषण लाइनें बिछाने का अधिकार देने के लिए जारी आदेश को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।2003 के अधिनियम की खंड 164 में क्या प्रावधान किया गया है, इसके संदर्भ से शक्ति के प्रभाव और विस्तार को समझा जा सकता हैः

164. कुछ मामलों में टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग।—

उपयुक्त सरकार, लिखित आदेश द्वारा, के लिए

विद्युत संचरण के लिए या कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या तार संचार के उद्देश्य से विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्रों को स्थापित करना, इस अधिनियम के तहत बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी भी लोक अधिकारी, लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो उपयुक्त सरकार अधिरोपित करना उचित समझे और भारतीय तार अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उन शक्तियों में से कोई भी जो

तार प्राधिकरण को उस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा स्थापित या बनाए गए तार के उद्देश्यों के लिए तार लाइनों और पदों को रखने के संबंध में प्राप्त हैं या इस तरह से स्थापित या बनाए रखा जाना है।

IV. टेलीग्राफ अधिनियम और बिजली अधिनियम, 1910 के अपवर्जन के तहत शक्तियां

(6) 1910 के अधिनियम को 2003 के अधिनियम की खंड 185 के तहत प्रदान की गई सीमा तक सहेजा गया है। जिस हद तक पारेषण लाइनों के लिए यह आवश्यक है, प्रासंगिक प्रावधान को पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

185. निरस्त करें और बचत करें।— (1) अन्यथा दिए गए रूप में सहेजें

यह अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9), विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं।(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, -

(क) कुछ भी किया गया है या कोई कार्रवाई की गई है या की गई है या की गई है या की गई है, जिसमें कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण आदेश या की गई या जारी की गई सूचना या कोई नियुक्ति, पुष्टि या घोषणा या कोई 621 शामिल है।

कंवर सिंह बनाम भारत का संघ अन्य का संघ

(के. कन्नन, जे.)

लाइसेंस, अनुमति, प्राधिकरण या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या साधन या निरस्त कानूनों के तहत दिया गया कोई निर्देश, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह माना जाएगा कि इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया है या लिया गया है।

(ख) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 18 में निहित प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम की धारा 67 से 69 के तहत नियम नहीं बनाए जाते।

(7) 1910 के अधिनियम की खंड 12 में भूमि के मालिक के लिए प्रतिष्ठानों पर आपत्ति करने और लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति की भूमि पर प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण शामिल हैं।इसमें लिखा हैः

खंड 12.सड़कों, रेलवे और ट्रामवे को खोलने और तोड़ने के बारे में प्रावधान

(आई)।

(2) उप-धारा (1) में निहित कोई भी बात किसी अनुज्ञप्तिधारी को, स्थानीय प्राधिकारी या संबंधित स्वामी [या] अधिभोगकर्ता की सहमति के बिना, किसी भी इमारत में, उसद्वारा से या उसके खिलाफ, या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित किसी भूमि पर या उसके नीचे, जिस पर या जिसके तहत कोई विद्युत आपूर्ति-लाइन या काम पहले से ही ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित या स्थापित नहीं किया गया है, कोई विद्युत आपूर्ति-लाइन या अन्य काम बिछाने या रखने के लिए अधिकृत या सशक्त नहीं मानी जाएगीःबशर्ते कि किसी [ऊपरी रेखा] का कोई समर्थन या किसी [ऊपरी रेखा] के किसी भी समर्थन को स्थिति में सुरक्षित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए आवश्यक कोई ठहराव या स्ट्रट किसी भी भवन या भूमि पर तय किया जा सकता है या, इस तरह तय किए जाने के बाद, ऐसे भवन या भूमि के मालिक या अधिभोगियों की आपत्ति के बावजूद, परिवर्तित किया जा सकता है, यदि जिला मजिस्ट्रेट या किसी प्रेसीडेंसी-टाउन [* * *] में, पुलिस आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देता हैःबशर्ते कि, यह भी कि यदि किसी भी समय किसी भवन या भूमि का मालिक या अधिभोगकर्ता, जिस पर ऐसा कोई सहारा, ठहराव या निर्माण तय किया गया है, पर्याप्त कारण दिखाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या,

प्रेसीडेंसी-टाउन [* * *], पुलिस आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी भी समर्थन, ठहराव या स्ट्रट को हटाने या बदलने का निर्देश दे सकता है।

(8) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह खंड 2003 के अधिनियम की खंड 67 के तहत नियम बनाए जाने तक ही सक्रिय होगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2006 से 2006 के नियम बनाए हैं और इसलिए 1910 के अधिनियम के प्रावधानों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। पुनः 2006 के नियमों को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां 2003 के अधिनियम की खंड 164 के तहत लाइसेंसधारी को शक्ति प्रदान की गई है, जैसा कि 2006 के नियमों के नियम 3 (4) में कहा गया है।खंड 164 अनुज्ञप्तिधारक को टेलीग्राफ अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार देती है। नतीजतन, यह टेलीग्राफ

अधिनियम है कि हमें लाइसेंसधारी की शक्तियों के विस्तार को समझने के लिए मुड़ना होगा।1910 के अधिनियम की खंड 12 को उपरोक्त खंडओं के संयुक्त पठन द्वारा पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

V. टेलीग्राफ अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी की शक्तियां भूमि मालिक द्वारा किसी भी आपत्ति की गुंजाइश को बाहर करती हैं

(9) 2003 के अधिनियम की खंड 164 लाइसेंसधारी को पारेषण लाइनें बिछाने के लिए टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार देती है। टेलीग्राफ अधिनियम की खंड 10 से 19 शक्ति की सीमा को चित्रित करती है और केवल हमारे उद्देश्य के लिए खंड 10 प्रासंगिक है और इसलिए पुनः प्रस्तुत की गई हैः

10. तार प्राधिकरण को रखने और बनाए रखने की शक्ति

टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट।— टेलीग्राफ प्राधिकरण समय-समय पर

किसी भी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ या उसके पार एक टेलीग्राफ लाइन का समय, स्थान और रखरखाव, और उसमें या उस पर पोस्ट करनाः

बशर्ते कि -

(क) तार प्राधिकरण इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या बनाए गए तार के उद्देश्यों के अलावा नहीं करेगा, या इस तरह से स्थापित या बनाए रखा जाएगा;

(बी) [केंद्र सरकार] केवल उस संपत्ति में उपयोगकर्ता के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं करेगी, जिसके तहत, उसके ऊपर, साथ, पार, या जिस पर टेलीग्राफ प्राधिकरण कोई टेलीग्राफ लाइन या पोस्ट रखता है; और 623

(ग) इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अलावा, टेलीग्राफ प्राधिकरण किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में या उसके नियंत्रण या प्रबंधन में निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग उस प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं करेगा; और

(घ) इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तार प्राधिकरण जितना संभव हो उतना कम नुकसान करेगा, और जब उसने खंड (ग) में निर्दिष्ट संपत्ति के अलावा

किसी अन्य संपत्ति के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग किया है, तो उन शक्तियों के प्रयोग के कारण उन्हें हुए किसी भी नुकसान के लिए इच्छुक सभी व्यक्तियों को पूरा मुआवजा देगा।

(क) टेलीग्राफ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार का संदर्भ अप्रासंगिक है- याचिकाकर्ता के तर्क को अस्वीकार करना, आधार

(10) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील का तर्क है कि टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को शामिल करने का एकमात्र तरीका खंड 10 के तहत लाइसेंसधारी को प्रतिस्थापित करना होगा, लेकिन जहां तक खंड केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले कार्यों पर विचार करती है, तब तक लाइसेंसधारी को शक्तियों का उपयोग करने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि केंद्र सरकार विद्युत लाइनों को स्थापित या बनाए नहीं रखती है।मैं इस तर्क को अस्वीकार करता हूं क्योंकि यह टेलीग्राफ अधिनियम के तहत शक्ति को अर्थहीन बनाता है। संवैधानिक योजना के तहत, तार का विषय प्रविष्टि 31, सूची 1 के रूप में आता है और अनिवार्य रूप से, केंद्र सरकार अकेले बिजली लाइनों की स्थापना और रखरखाव कर सकती है।लेकिन बिजली का विषय सूची 3 में प्रविष्टि 38 के तहत निहित है, जो समवर्ती सूची में है और खंड 164 के तहत आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकरण है। 'उपयुक्त प्राधिकारी' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

खंड 2.परिभाषाएँ

(5) “उपयुक्त सरकार का अर्थ है, (ए) केंद्र सरकार, (आई) पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसके स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनी के संबंध में;

((ख) किसी भी अंतर-राज्यीय उत्पादन, पारेषण, व्यापार या बिजली की आपूर्ति के संबंध में और किसी भी खान, तेल क्षेत्र, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, तार, प्रसारण स्टेशन और रक्षा, डॉकयार्ड, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों के किसी भी कार्य के संबंध में;

((ग) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र के संबंध में;

((iv) उससे संबंधित या उसके नियंत्रण में किसी भी कार्य या विद्युत स्थापना के संबंध में;

(ख) किसी अन्य मामले में, इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र वाली राज्य सरकार

(11) 9 दिसंबर 2010 के आदेश के तहत अधिसूचित संचरण योजना एक अंतर-राज्य संचरण लाइन है और इसलिए उपयुक्त प्राधिकरण केवल राज्य सरकार है। जब खंड 164 अनुज्ञप्तिधारक को टेलीग्राफ अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है, तो टेलीग्राफ लाइनों के संदर्भ को विद्युत लाइनों के लिए आवेदन के रूप में समझा जाना चाहिए और केंद्र सरकार को टेलीग्राफ लाइनों को स्थापित करने और बनाए रखने की शक्ति को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसका अर्थ राज्य सरकार को बिजली लाइनों को स्थापित करने और बनाए रखने की शक्ति है। निगमन के सिद्धांत के संबंध में वैधानिक व्याख्या को तर्क में पूरी तरह से किया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा, बिजली की लाइनों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की तलाश करना हास्यास्पद तर्क होगा जो वह राज्य के साथ स्थापित या बनाए नहीं रखती है।

VI. पारेषण लाइन बिछाने की शक्ति के लिए हमेशा संपत्ति के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है

(12) याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि ऐसी संपत्ति के लिए एक संवैधानिक संरक्षण है जिसे कानून के तहत अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 300 ए के तहत प्रदान किया गया है और लाइसेंसधारी के लिए भूमि पर प्रवेश करने और प्रतिष्ठान बनाने का कोई अधिकार मौजूद नहीं हो सकता है, जिसमें कृषि भूमि में प्लेटफार्मों और खंभों का निर्माण शामिल है, जिसका प्रभाव उनकी भूमि को अनुपलब्ध बनाने से होता है, जिस पर प्रतिष्ठान बनाए जाते हैं। वकील ने 2003 के अधिनियम की खंड 165 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 40 और 41 संपत्ति के अधिग्रहण पर लागू होती हैं जो उन स्थितियों में अपरिहार्य है जहां ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाती हैं।

इन प्रावधानों के दायरे को समझने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

विद्युत अधिनियम, 2003:165 अधिनियम की धारा 40 और 41 का संशोधन

1 1894 में।— (1) खंड 40 में, खंड (बी) की उप-खंड (1)

और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 41, उप-खंड (5), "कार्य" शब्द में निर्माण किए जाने वाले कार्य के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली या आपूर्ति की जाने वाली बिजली शामिल मानी जाएगी।

(2) उपयुक्त सरकार, इस संबंध में उपयुक्त आयोग की सिफारिश पर, यदि वह उचित समझती है, किसी व्यक्ति के आवेदन पर, जो अपने उद्देश्यों के लिए कोई भूमि प्राप्त करने की इच्छुक कंपनी नहीं है, निर्देश दे सकती है कि वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि का अधिग्रहण उसी तरीके से और उन्हीं शर्तों पर कर सकती है जैसे कि उस व्यक्ति के कंपनी होने पर किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियमः40. पिछली पूछताछ।— (1) ऐसी सहमति

यह तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उपयुक्त सरकार को खंड 5-ए, उप-खंड (2) के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट पर या इसके बाद दी गई जांच द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता है, -

(क) कि अधिग्रहण का उद्देश्य कंपनी द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए आवासों के निर्माण के लिए या उससे सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए भूमि प्राप्त करना है, या

((क) कि ऐसा अधिग्रहण किसी ऐसी कंपनी के लिए किसी भवन या कार्य के निर्माण के लिए आवश्यक है जो किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी उद्योग या कार्य में लगी हुई है या खुद को संलग्न करने के लिए कदम उठा रही है, या]

(ख) कि किसी कार्य के निर्माण के लिए इस तरह के अधिग्रहण की आवश्यकता है, और यह कि ऐसा कार्य जनता के लिए उपयोगी साबित होने की संभावना है।]

(2) ऐसी जाँच ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसे समय और स्थान पर [उपयुक्त सरकार] नियुक्त करेगी।

(3) ऐसा अधिकारी गवाहों को तलब कर सकता है और उनकी उपस्थिति को लागू कर सकता है और उसी माध्यम से और जहां तक संभव हो, उसी तरीके से दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर कर सकता है जैसा कि सिविल कोर्ट के मामले में [सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908] द्वारा प्रदान किया गया है।

41. उपयुक्त सरकार के साथ समझौता।— अगर

उपयुक्त सरकार खंड 5-ए, उप-खंड (2) के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद या खंड 40 के तहत जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर संतुष्ट होती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण खंड 40 की उप-खंड (1) के खंड (ए) या खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए है, इसके लिए कंपनी से [उपयुक्त सरकार] के साथ एक समझौता करने की आवश्यकता होगी, जिसमें निम्नलिखित मामलों के लिए [उपयुक्त सरकार] की संतुष्टि के लिए प्रावधान किया जाएगा, अर्थात् -

(1) अधिग्रहण की लागत का [उपयुक्त सरकार को भुगतान];

(2) कंपनी को ऐसे भुगतान पर भूमि का अंतरण; (3) वे शर्तें जिन पर कंपनी द्वारा भूमि धारण की जाएगी; (4) जहां अधिग्रहण आवास-निर्माण या उससे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के उद्देश्य से किया गया है, वह समय जिसके भीतर, वे शर्तें जिन पर और जिस तरीके से आवास या सुविधाएं खड़ी की जाएंगी या प्रदान की जाएंगी;

(4-(क) जहां अधिग्रहण किसी ऐसी कंपनी के लिए किसी भवन या कार्य के निर्माण के लिए है जो किसी ऐसे उद्योग या कार्य में लगी हुई है या खुद को शामिल करने के लिए कदम उठा रही है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें जिनके आधार पर भवन या कार्य का निर्माण या निष्पादन किया जाएगा; और

(5) जहाँ अधिग्रहण किसी अन्य कार्य के निर्माण के लिए है, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें जिन पर कार्य निष्पादित और बनाए रखा जाएगा, और वे शर्तें जिन पर जनता कार्य का उपयोग करने की हकदार होगी।]

कंवर सिंह बनाम भारत का संघ अन्य का संघ

(के. कन्नन, जे.)

(13) इन प्रावधानों को उचित सरकार को कार्यों को पूरा करने के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सशक्त बनाने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और जब ऐसा

अधिग्रहण किया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 40 और 41 के तहत प्रावधान लागू होंगे।ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ उस क्षेत्र के साथ, जिस पर पारेषण लाइनें बिछाई जाती हैं, एक उप-स्टेशन का कहना है कि लाइसेंसधारक को बड़ी संरचनाओं और भवनों को खड़ा करने की आवश्यकता हो सकती है।एक सुविधाजनक प्रावधान जैसे कि यह है, कोई अधिदेश नहीं है कि किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा।जिस हद तक जमीन के मालिक को कोई नुकसान होता है या ऊपर के तारों के नीचे या उस स्थान पर जहां बिजली के खंभे या मीनार या ठहराव या स्ट्रट लगाए गए हैं, वहां तुरंत खेती करने में असमर्थ होने से आय का नुकसान होता है, मुआवजे का प्रावधान है।अनुच्छेद 19 (च) के निराकरण के बाद संपत्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार के प्रयोग का प्रावधान करता है जिसे कानून के अधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि विद्युत अधिनियम और टेलीग्राफ अधिनियम जैसे कानून एक उपयुक्त सरकार और लाइसेंसधारी को विद्युत लाइन स्थापित करने के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देते हैं, तो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक प्राधिकरण से मांग करने का वैधानिक प्रावधानों के समयबद्ध पालन से अधिक कोई अधिकार नहीं है।याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि टेलीग्राफ लाइनों के लिए खंभे बिजली की लाइनों के लिए टावरों की तुलना में पतले और/या छोटे हैं और इसलिए उन्हें संपत्ति प्राप्त किए बिना स्थापित करने की शक्ति नहीं हो सकती है, सही नहीं है।टावरों की स्थापना सांविधिक रूप से उन व्यक्तियों की भूमि पर अनिवार्य लाइसेंस के रूप में संरक्षित है जहां प्रतिष्ठान बनाए गए हैं और लाइनों को स्थापित करने के लिए इस तरह की शक्ति के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है।

VII. आवश्यकतानुसार मुआवजा टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से होगा न कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत।

(14) शक्ति की सीमा को टेलीग्राफ अधिनियम की खंड 16 द्वारा से देखा जा सकता हैः

16. खंड 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और मुआवजे के रूप में विवाद, एक के अलावा अन्य संपत्ति के मामले में

स्थानीय प्राधिकरण।— (1) यदि उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग

उस खंड के खंड (घ) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में खंड 10 में विरोध किया जाता है या बाधित किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेक से आदेश दे सकता है कि टेलीग्राफ प्राधिकरण को उनका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) यदि, उप-खंड (1) के तहत आदेश देने के बाद, कोई व्यक्ति उन शक्तियों के प्रयोग का विरोध करता है, या संपत्ति पर नियंत्रण रखने वाला, उनके प्रयोग के लिए सभी सुविधाएं नहीं देता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की खंड 188 के तहत अपराध करने वाला माना जाएगा।

(3) यदि खंड 10, खंड (घ) के तहत भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की पर्याप्तता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यह विवादित पक्षों में से किसी एक द्वारा इस उद्देश्य के लिए उस जिला न्यायाधीश को आवेदन करने पर, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) यदि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, या उस अनुपात के बारे में जिसमें इच्छुक व्यक्ति उसमें भाग लेने के हकदार हैं, तो तार प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के न्यायालय को ऐसी राशि का भुगतान कर सकता है जो वह पर्याप्त समझता है या, जिसके सभी विवादित पक्षों ने लिखित रूप में स्वीकार किया है कि बोली की गई राशि पर्याप्त है या राशि उप-धारा (3) के तहत निर्धारित की गई है, वह राशि; और जिला न्यायाधीश, पक्षों को नोटिस देने और उनमें से ऐसे लोगों की सुनवाई करने के बाद, जो सुनवाई की इच्छा रखते हैं, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों या, जैसा भी मामला हो, उस अनुपात का निर्धारण करेगा जिसमें इच्छुक व्यक्ति इसमें भाग लेने के हकदार हैं।

(5) उप-खंड (3) या उप-खंड (4) के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा विवाद का प्रत्येक निर्धारण अंतिम होगाःबमुकदमो कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के उस व्यक्ति से, जिसने उसे प्राप्त किया है, टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए गए किसी मुआवजे के पूरे या किसी हिस्से की वसूली करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।(15) मुआवजे की मांग करके संबंधित मालिक द्वारा जिस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, वह टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से होगा। याचिकाकर्ताओं के पास अभी भी ऊपर दिए गए तरीके से इस तरह के दावे करने का

समय है।याचिकाकर्ताओं की आगे की आपत्तियाँ यह हैं कि उन्हें प्रतिष्ठानों का विवरण प्रदान नहीं किया गया था और सार्वजनिक सूचना में दिए गए पते में राज्य की सीमा के बाहर गुजरात में लाइसेंसधारी का पता दिया गया था और इसलिए वे प्रभावी रूप से अपनी आपत्तियाँ नहीं दे सके।नोटिस जारी करने का कोई विशेष तरीका नहीं है।यदि सार्वजनिक सूचना प्रभावित गाँवों को प्रदान करती है और यह 629 के साथ भी प्रदान करती है

कंवर सिंह बनाम भारत का संघ अन्य का संघ

(के. कन्नन, जे.)

जानकारी कि गाँव के लोग जो प्रभावित हो सकते हैं, वे एक निर्दिष्ट पते और स्थान से आरेख प्राप्त कर सकते हैं, जो सामान्य रूप से पर्याप्त होना चाहिए।हालाँकि, इस आपत्ति में कुछ योग्यता है कि यदि लाइसेंसधारी का पता राज्य के बाहर है, तो सरकार को खंड 164 के तहत आदेश जारी करते समय यह शर्त भी लागू करनी चाहिए कि लाइसेंसधारी एक स्थानीय संपर्क पता प्रदान करता है जो जनता के किसी भी सदस्य के लिए वास्तव में कार्यालय में जाने और विवरण एकत्र करने और मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई के लिए आपत्तियाँ करने के लिए आसानी से सुलभ हो।इस मामले में, एक शिकायत के अलावा कि लाइसेंसधारी राज्य से बाहर है, यह तर्क नहीं है कि जब आरेखों की मांग की गई थी या जब प्रतिष्ठानों के विवरण की आवश्यकता के लिए एक संचार भेजा गया था, तो 5 वें प्रतिवादी ने अनुरोधों का पालन नहीं किया था।दूसरी ओर, 5 वें प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील बताते हैं कि सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की खंड के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जिसमें शामिल हैंः(क) एक प्रारूप में प्रकाशन द्वारा से संचरण योजना का प्रकाशन (ख) जिस पते पर विवरण प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही आपत्तियां विचार के लिए दी जा सकती हैं और (ग) दस्तावेजों की प्रतियों की प्राप्ति की स्वीकृति के लिए प्रारूप।ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया है कि सरकार के किसी भी दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया है।भविष्य के मार्गदर्शन के लिए एक उपाय के रूप में, मैं राज्य सरकार को निर्देश दूंगा कि वह आपत्तियों के लिए प्रावधान करे और प्रभावित पक्षों के लिए संचरण योजना का विवरण प्राप्त करे, जिसमें लाइसेंसधारियों को राज्य के भीतर गांवों या उनके आसपास के क्षेत्र में एक स्थानीय पता देने पर जोर दिया जाए जहां संचरण लाइनें बिछाई गई हैं।अभी तक, किसी भी कानूनी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए मुझे यह मानने का कोई कारण नहीं मिलेगा कि प्रतिवादी के कार्यों को दूषित किया गया है।

VIII. यह आपत्ति कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है, याचिकाकर्ता को लाभान्वित करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है

(16) याचिकाकर्ता के वकील का आग्रह है कि 1 से 4 प्रतिवादी, जो राज्य के पदाधिकारी हैं, ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।मेरा मानना है कि यह अप्रासंगिक है कि जो व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी है, वह व्यक्ति जो प्रभावित पक्षकार है, क्योंकि वह राज्य की ओर से सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है और जब तक राज्य 5 वें प्रत्यर्थी के किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं करता है, तब तक याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं के अधिकारों से इनकार करते हुए प्रतिवादी अभाव में राज्य या अनुज्ञप्तिधारी के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष से अपने लिए कोई लाभ नहीं हो सकता है।

IX. उद्धृत पूर्व निर्णय पर विचार किया गया

(17) मैंने अब तक सभी मुद्दों पर वैधानिक प्रावधानों और कानून के पहले सिद्धांतों के संदर्भ में विचार किया है।जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, 2003 के अधिनियम के लागू होने के बाद यह एक अज्ञात मार्ग है।जहाँ तक उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात है, विचार करने का एक अवसर आया

प्रबंध निदेशक रामकृष्ण पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम

आर. चेल्लप्पन (1), लेकिन अंततः निर्णय पक्षों के बीच कुछ सहमत रेखाओं पर दिया गया जब कुछ पोल्ट्री शेड के ऊपर ओवरहेड लाइनों को एक विशेष ऊंचाई से ऊपर उठाने पर सहमति व्यक्त की गई ताकि पशुधन को कोई खतरा न हो और इस प्रकार शेड के मालिक की आपत्तियों को संबोधित किया गया।इस विषय पर कम से कम दो अधिकार हैं।केरल उच्च न्यायालय ने भारत प्लाईवुड में अपने फैसले द्वारा से और

टिंबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल एसईबी (2), आंध्र

जी. वी. एस. रामकृष्ण बनाम में अपने फैसले द्वारा से प्रदेश उच्च न्यायालय

प्रबंध निदेशक A.P.Transoco (3), आशीष कुमार घोष बनाम सीईएससी लिमिटेड (4) में कलकत्ता उच्च न्यायालय, जयंतकुमार भागूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (5) में

गुजरात उच्च न्यायालय, रजक बनाम एनटीपीसी (6) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्निमलई गौंडर बनाम तमिलनाडु सरकार (7) में मद्रास उच्च न्यायालय;

कानविझी बनाम टी. एन. ई. बी. (8) अजय मुंजाल में झारखंड उच्च न्यायालय

मेमोरियल ट्रस्ट बनाम पावर ग्रिड सी संगठन (9) ने बरकरार रखा है

निजी विरोधियों पर सार्वजनिक हित की प्रधानता और निजी भूमि मालिकों की आपत्तियों के बावजूद ओवरहेड तार बिछाने के लिए राज्य या उसके लाइसेंसधारी के अधिकार को मान्यता दी और आपत्ति पर निर्णय लेने और उसे पूरा करने के लिए कार्यकारी कार्य द्वारा शासित आपत्तियों की सीमा को सीमित किया।

(1) (2009) 16 एस. सी. सी. 743

(2) AIR 1972 केर (47 (FB) (3) AIR 2009 AP 158 (4) AIR 2004 Cal 130 (5) AIR 2007 गुजरात 32 (6) AIR 1988 MP 172 (7) AIR 2001 मैड 98 (8) AIR 2008 NOC 1323 (9) AIR 2008 झा 34 631

कंवर सिंह बनाम भारत का संघ अन्य का संघ

(के. कन्नन, जे.)

देय मुआवजे के विचार से परे आपत्तियों द्वारा अनियंत्रित योजना।दिल्ली उच्च न्यायालय ने एस. उरात सिंह बनाम दिल्ली मामले में एक निर्णय में

नगर निगम (10) और पटना उच्च न्यायालय ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनाम राम नरेश सिंह (11) मामले में यह फैसला सुनाया है।

निजी मालिकों की पूर्व सहमति के बिना रेखाएं नहीं खींची जा सकती थीं।दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के दावे के संदर्भ में दिया गया था।पटना उच्च न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाई गई इसी तरह की आपत्तियों पर विचार किया।इस संबंध में मेरा विचार है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में उपरोक्त अनुच्छेदों में उल्लिखित विभिन्न आधारों की सही व्याख्या नहीं है और उन्हें यहाँ दोहराने का कोई कारण नहीं मिलेगा।विभिन्न उच्च न्यायालयों से न्यायिक राय की पूर्व-प्रतिक्रिया भूमि मालिक की पूर्व सहमति के बिना मुख्य संचरण लाइनों को बिछाने की लाइसेंसधारी की शक्ति को बरकरार रखती है और मैं इस तरह के तर्क को बरकरार रखता हूं।

एक्स. स्वभाव

(18) सभी रिट याचिकाओं का यह मानते हुए निपटारा किया जाता है कि 5 वें प्रतिवादी की कार्रवाई कानून के अनुरूप है और मुआवजे के दावों को ऊपर निर्दिष्ट टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से स्वतंत्र रूप से निपटाया जाएगा। पाँचवें प्रतिवादी के कार्यों पर रोक लगाने वाली रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश खाली कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह राज्य के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय पते के लिए गांवों में या उचित निकटता में उचित शर्तें निर्धारित करे, जहां भूमि मालिक अधिसूचना के अनुसार संचरण योजना का विवरण एकत्र कर सकते हैं, अपनी आपत्तियां आदि को निष्पक्षता के उपाय के रूप में रख सकते हैं और भविष्य के सभी लेन-देनों में सार्वजनिक सूचना को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और वर्तमान में, यह पता लगाने के लिए कि अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों या आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ताकि रिट याचिकाओं के लिए वाद हेतुक एक वैध कारण पाया जा सके।

ए. एजीजी।

(10) ए. आई. आर. 1989 डेल 51 (11) ए. आई. आर. 2011 पैट 83

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur